मुख्यमंत्री ने बांदीकुई में 607 करोड़ रूपए के 213 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

ज्योतिबा फुले की 200वीं जयन्ती पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महात्मा फुले के मिशन को आगे बढ़ाया

दौसा/जयपुर,11अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन महिला, किसान, मजदूर समेत शोषित एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महात्मा ज्योतिबा फुले के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक एकता और समरसता के मार्ग पर चलकर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

शर्मा ने शनिवार को बांदीकुई में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती एवं विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ज्योतिबा फुले को सच्चा महात्मा कहा था। वहीं, बाबा साहेब ने इनको अपने तीन गुरुओं में से एक माना था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पिछड़ों और महिलाओं के मन में सामाजिक न्याय और शिक्षा की ज्योति जलाई। उन्होंने सामाजिक सुधार की शुरूआत सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को शिक्षित कर की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बांदीकुई में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दौसा जिले के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर दौसा जिले में 607.66 करोड़ रुपये की लागत से 213 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इनमें ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, स्कूल शिक्षा, स्वायत्त शासन, वन, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, आयुर्वेद, ग्रामीण विकास, जल संसाधन एवं सहकारिता विभाग के विकास कार्य शामिल हैं।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर किया। उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में ''सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी'' तथा समस्त जिलों में ''महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय'' की स्थापना करने की घोषणा की।

शर्मा ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर करने, बांदीकुई दौसा रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण तथा बांदीकुई एवं बसवा नगरपालिका में सीवरेज व ड्रेनेज गैप के कार्य स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों एवं युवाओं की शिक्षा के साथ विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी' की स्थापना एवंसमस्त जिलों में 'महात्मा ज्योतिबा फुलेआदर्श विद्यालय' स्थापित करने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, विधायक भागचंद टांकड़ा, राजेन्द्र मीना, रामविलास मीना, विक्रम बंशीवाल, हंसराज मीना, देवी सिंह शेखावत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

'हमारे इरादे नेक हैं, पर, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बकर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। वे शुक्रवार को पाकिस्तानी राजधानी में पहुँच गये।

पाकिस्तान की ओर जाते समय वैंस ने कहा कि उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने आगे कहा, ''अगर वे हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें यह पता चलेगा कि वार्ता करने आई टीम उसे स्वीकार करने वाली नहीं है।''

ईरानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख गलीबाफ ने भी सतर्क रुख अपनाया और कहा, ''हमारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं करते।''

ईरानी टीवी के अनुसार, गलीबाफ ने कहा, ''अमेरिका के साथ हमारी समर्ताता वार्ता हमेशा असफल तथा टूटने वाले वादों से भरी रही है।''

तेहरान ने कहा कि वार्ता तभी शुरू होगी, जब वॉशिंगटन उसकी शर्तों को स्वीकार करेगा, जिनमें लेबनान में युद्धिवराम और ईरान के फंसे हुए संसाधनों की रिहाई शामिल है। उल्लेखनीय है कि इज़राइल ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धिवराम लेबनान पर लागू नहीं होता।

इस बीच, शनिवार को ट्रंप ने होर्मुज़ स्ट्रेट के रणनीतिक महत्व को कम करके दिखाते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया कि कई खाली तेल टैंकर, जिनमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े टैंकर भी शामिल हैं, वर्तमान में अमेरिका जा रहे हैं, ताकि सबसे ''बेहतरीन'' और ''शानदार'' तेल और गैस लोड की जा सके। उन्होंने ट्रुथ स्पेशल पर कहा कि अमेरिका के पास दो सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के संयुक्त उत्पादन से अधिक तेल है।

यह बयान वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में बढ़ी अस्थिरता के समय आया है, जहां टैंकरों की गतिविधियां होर्मुज़ स्ट्रेट में व्यवधान और अमेरिका-ईरान संघर्ष से जुड़ी हैं। जहां तक ट्रंप के उस दावे की बात है कि अमेरिका के पास दो सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के संयुक्त उत्पादन से अधिक तेल है, डेटा उन्हें आंशिक रूप से सही बताता है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, जबकि अमेरिकी तेल मुख्य कच्चे तेल की कीमतों को यथावत रख सकेगा।

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन 2026 के आँकड़ों में देश के कुल पेट्रोलियम तरल पदार्थ के उत्पादन को लगभग 22 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। यह आँकड़ा अमेरिका को, रूस और सऊदी अरब के संयुक्त उत्पादन के बराबर या उससे थोड़ा आगे रखता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जारी संघर्ष के दौरान ऊर्जा को बार-बार रणनीतिक और आर्थिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। हाल ही में उन्होंने पश्चिम एशियाई देश की आलोचना की है कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट में टैंकरों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर रहा है, और चेतावनी दी कि तेल ''ईरान के सहयोग तथा उसके बिना भी'' प्रवाहित रहेगा।

ट्रंप ने अपने पोस्ट में खुले तौर पर लेन-देन वाले स्वर में अमेरिका के तेल को वैश्विक खरीदारों के सामने प्रस्तुत किया। टैंकरों के लिए उनके निमंत्रण और त्वरित कार्यवाही का वादा अमेरिकी वर्चस्व को तेल की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों में बेहतर बताने का उद्देश्य लिए हुए था, जबकि वैश्विक बाजार वार्ता के बीच अस्थिर बने हुए हैं।

यह पोस्ट ट्रंप के पहले के बयानों की पृष्ठभूमि में आई है, जिनमें उन्होंने कहा था कि वे ''तेल अपने पास रखना'' और ईरान जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों से बहुत पैसा कमाना पसंद करेंगे, तब उन्होंने खुद को ''व्यवसायी'' के रूप में प्रस्तुत किया था।

अमेरिका-ईरान वार्ता शुरु हुई, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समर्थकों पर हमले बंद होने चाहिए।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने इज़राइल से कहा कि वह लेबनान पर हमलों में कमी करे और इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें इसके अनुसार कदम उठाना पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिणी लेबनान पर, जहां हिज़बुल्लाह की सेनाएँ है, इज़रायल के हमले रुक गए हैं।

हालाँकि, अब तक ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के आ ान को लगभग नज़रअंदाज़ किया है। डॉनल्ड ट्रंप पहले इस बात पर ज़ोर दे चुके थे कि होर्मुज़ स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में मुक्त करना वार्ता की प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन यह मुद्दा कम से कम सार्वजनिक रूप से नज़रअंदाज़ किया गया है।

डॉनल्ड ट्रंप के हाथ धीरे-धीरे बंधते जा रहे हैं और यह स्थिति उन्हें ईरान की मांगों के प्रति झुकने पर मजबूर कर रही है। अमेरिका में महँगाई तेजी से बढ़ रही है और युद्ध जारी रहने से स्थिति और खराब हो सकती है। मार्च में ही कीमतें लगभग 1 प्रतिशत बढ़ी और वार्षिक महँगाई 3.3 प्रतिशत है।

वार्ता दो एक्शन एजेंडा के इर्द-गिर्द चल रही है, एक अमेरिका की तरफ से 15 मांगों के साथ, दूसरा ईरान की तरफ से 10-बिंदु एजेंडा, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईरान का छोटा एजेंडा सबसे ज्यादा चर्चा में है।

ईरान ने यह भी मांग की कि उसकी शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। ईरान 3.6 प्रतिशत तक यूरेनियम एनरिचमैंट का अधिकार चाहता है, जो नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है।

साथ ही, ईरान के पास उच्च समृद्ध यूरेनियम का भंडार है, जो परमाणु हथियारों में इस्तेमाल योग्य है। अमेरिका मांग कर रहा है कि ये भंडार उसे सौंप दिए जाएँ और ईरान सहमत हो कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। यह ईरान के लिए नई बात नहीं है और इस शर्त से उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का अधिकार प्रभावित नहीं होता।

वार्ता मुख्य रूप से नियमित कूटनीतिककर्मियों और उनके पारंपरिक तरीकों को बायपास करते हुए की जा रही है। उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस के लिए यह नया काम है और वे इसके लिए ठीक तरह से तैयार प्रतीत होते हैं। इसमें निश्चित रूप से स्पष्टता की आवश्यकता है।

प्र.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संक्षेप में ध्यान दिया, जो संसद की सामान्य कार्यवाही से अलग और दिलचस्प था।

विज़ुअल पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक्स पर एक यूज़र ने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ गंभीर बातचीत में लगे हुए हैं, और ऐसे क्षणों का प्रतीकात्मक महत्व गहन ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण है।

खेड़ा को मिली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनके परिवार के बारे में खेड़ा द्वारा दिए गए बयानों के कारण दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति के सुजाना ने कहा कि भले ही एफआईआर असम में दर्ज हो, पर अदालत सीमित सुरक्षा दे सकती है, उन्होंने इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के अंतरराज्यीय मामलों में ट्रांज़िट जमानत के फैसलों का हवाला दिया। न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि खेड़ा ने गिरफ्तारी का युक्तिसंगत भय दिखाया है, विशेष रूप से तब जब असम और दिल्ली पुलिस द्वारा उनके दिल्ली निवास पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई। यह मामला 4 अप्रैल को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया, जिसमें खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने सरमा पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया। इसके बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की गई, जिससे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह राहत अस्थायी है, ताकि खेड़ा सात दिनों के भीतर असम की सक्षम अदालत से नियमित अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकें।

सोने के खनन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्य राष्ट्र अपने खनन कोड को सरल बना चुके हैं, ताकि गहरी खदानों की खोज के लिए आवश्यक अरबों रुपये के पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके, वहीं भारत उपनिवेशकालीन नौकरशाही में फंसा हुआ है, जो हर खनिज जमा को राष्ट्रीय संपत्ति के बजाय संभावित विवाद के रूप में देखता है।

ईरान मान भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उचित विचार के साथ होगा। अमेरिकी अधिकारी इस बयान को खानें हटाने की कठिनाइयों की स्वीकरोक्ति के रूप में देख रहे हैं। नौसैनिक खानों को हटाना स्पष्ट रूप से एक जटिल मुद्दा है। दुनिया की उन्नत सेनाओं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, के पास बड़े पैमाने पर खान सफाई के संसाधन नहीं हैं। रिपोर्टों के अनुसार, स्थिति और जटिल इसलिए भी हो गई है, क्योंकि अमेरिकी हमलों में ईरान के नौसैनिक बुनियादी ढांचे और जहाजों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। इसलिए, न तो ईरान और न ही अमेरिका के पास इसकी स्पष्ट जानकारी है कि होर्मुज़ में कितनी खानों का अस्तित्व है, इस स्थिति के कारण वैश्विक शिपिंग के लिए गंभीर जोखिम है और दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग के पूर्ण रूप से पुनः खुलने में देरी होना स्वाभाविक है।

राहुल गांधी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब यदि राहुल ओबीसी एजेंडे के लिए आक्रामक रूप से प्रयास नहीं करते हैं, तो यह उनके लिए बड़ी समस्याएँ खड़ी करेगा; और यदि वे इसे उठाते हैं तो ऐसा लगेगा कि वे ओबीसी और दलित मुद्दों के बीच भ्रमित हैं। विशेष सत्र के तीन दिनों में भारी बहस और हंगामा होने की संभावना है, लेकिन मुख्य सवाल यह बना हुआ है कि क्या भाजपा बिल को पास करा पाएगी। धारणा की लड़ाई जारी है, जिसमें प्रत्येक राजनीतिक दल तैयार है कि वह अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे और मजबूत संदेश भेजे कि वे वास्तव में देश के हित में काम करने वाले सच्चे नेता हैं।

अब बची छुट्टियों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाने के लिए सेवानिवृत्ति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह नियम पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। पहले, अधिकांश राज्यों में लीव एन्कैशमेंट केवल इस्तीफा देने या सेवानिवृत्ति के समय ही भुगतान योग्य था। अब कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में अपनी संचित छुट्टी के लिए भुगतान का अनुरोध कर सकेंगे। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की छुट्टी अगले वर्ष तक ले जा (संचित) सकते हैं। यदि आपकी संचित छुट्टी इस 30-दिन की सीमा से अधिक है, तो आपको कंपनी से उन अतिरिक्त दिनों के लिए वित्तीय मुआवजा प्राप्त होगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908